



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12052020-219357
CG-DL-E-12052020-219357

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 219]	नई दिल्ली, मंगलवार, मई 12, 2020/वैशाख 22, 1942
No. 219]	NEW DELHI, TUESDAY, MAY 12, 2020/VAISAKHA 22, 1942

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 मई, 2020

संख्या 22/2020-सीमा शुल्क

सा.का.नि. 293(अ).—जहां कि “रिफाईंड ब्लिचड डिओडोराइज्ड पामोलीन और रिफाईंड ब्लिचड डिओडोराइज्ड पाम ऑयल” (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत वस्तु से संदर्भित किया गया है), जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम से संदर्भित किया गया है) की प्रथम अनुसूची के टैरिफ मद [1511 90 10] या टैरिफ मद [1511 90 20] के अंतर्गत आते हैं, के आयात से संबंधित मामले में व्यापार उपचार महानिदेशालय ने भारत-मलेशिया बृहद् आर्थिक सहयोग करार (द्विपक्षीय सुरक्षा उपाय) नियमावली, 2017 (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त नियमावली से संदर्भित किया गया है) के नियम 9 के अनुसार प्रारंभिक मामला संख्या (SG) 04/2019, दिनांक 14 अगस्त, 2019, जिसे दिनांक 14 अगस्त, 2019 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग I, खंड 1 में प्रकाशित किया गया था, के तहत जांच का कार्य शुरू किया था;

और जबकि अधिसूचना (द्विपक्षीय सुरक्षा जांच) वाद संख्या (एसजी) 04/2019, दिनांक 26 अगस्त, 2019 जिसे दिनांक 26 अगस्त, 2019 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग I, खंड 1 में प्रकाशित किया गया था, के तहत जारी अपने प्राथमिक निष्कर्षों में उक्त निर्दिष्ट प्राधिकारी अपने इस प्रारंभिक निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि ऐसी विशेष परिस्थितियां विद्यमान हैं कि यदि सुरक्षा उपायों को लागू करने में विलम्ब होता है तो स्वदेशी उत्पादकों को अपूरणीय क्षति हो जाएगी और उन्होंने मलेशिया में मूलतः उत्पादित और भारत-मलेशिया बृहद् आर्थिक सहयोग करार (एतश्मिन पश्चात जिसे सीईसीए से संदर्भित

किया गया है)के अंतर्गत आरक्षित उक्त विषयगत वस्तु के आयात पर लगने वाले सीमा शुल्क की दर में 180 दिन के लिए 5 प्रतिशत की बढ़ोतरी करने की सिफारिश की है;

और जहां कि, उक्त निर्दिष्ट प्राधिकारी के उपर्युक्त निष्कर्षों के आधार पर, केन्द्र सरकार ने भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 53/2011-सीमा शुल्क, दिनांक 1 जुलाई, 2011 जिसे सा.का.नि. 499(अ), दिनांक 1 जुलाई, 2011 के तहत भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी संशोधन करते हुए भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 29/2019-सीमा शुल्क, दिनांक 4 सितम्बर, 2019, जिसे सा.का.नि. 632 (अ), दिनांक 4 सितम्बर, 2019 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा उक्त विषयगत वस्तु पर अनन्तिम रूप से द्विपक्षीय रक्षोपाय शुल्क को अधिरोपित किया था;

और जहां कि, उक्त निर्दिष्ट प्राधिकारी ने अधिसूचना (द्विपक्षीय रक्षोपाय जांच) वाद संख्या (एस.जी.) 04/19, दिनांक 28 फरवरी, 2020 जिसे दिनांक 28 फरवरी, 2020 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग I, खंड 1 में प्रकाशित किया गया था, के तहत जारी अपने अंतिम निष्कर्षों में इस बात को नोट किया है और सिफारिश की है कि –

- (क) जब जांच कार्य चल रहा था, उस समय सरकार ने अधिसूचना संख्या 39/2015-2020, दिनांक 8 जनवरी, 2010 के तहत एचएस कोड 1511 90 10 (रिफाइंड ब्लिचड डिओडोराइज्ड पाम आयल) एचएस कोड 1511 90 20 (रिफाइंड ब्लिचड डिओडोराइज्ड पामोलीन) और एचएस कोड 1511 90 90 (अन्य) के अंतर्गत आने वाले मदों से संबंधित आयात नीति में संशोधन कर दिया था और उक्त विषयगत वस्तु को “प्रतिबंधित” की श्रेणी में रख दिया था।
- (ख) दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन ‘एशियान’ के साथ भारतीय गणराज्य के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (एनशिमन पश्चात जिसे से ‘एशियान’ करार संदर्भित किया गया है) (जिसमें मलेशिया भी शामिल है) और सीईसीए के अंतर्गत लगाए जाने वाले आधारभूत सीमा शुल्क में 1 जनवरी, 2020 से परिवर्तन कर दिया गया था और इन दोनों ही करारों के अंतर्गत कच्चे पाम आयल और रिफाइंड पामोलीन/पाम आयल के बीच 7.5% का अंतर है।
- (ग) ‘एशियान’ करार के अंतर्गत इसी प्रकार के शुल्क को लगाए बिना वर्तमान करार के अंतर्गत रक्षोपाय शुल्क को लगाने का मतलब है इस रक्षोपाय शुल्क को बेकार कर देना क्योंकि उपभोक्ता तो ‘एशियान’ करार के अंतर्गत मिलने वाले लाभ का उपयोग कर लेंगे।
- (घ) उपर्युक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए यह विचार किया गया है कि अधिसूचना संख्या 29/2019-सीमा शुल्क, दिनांक 4 सितम्बर, 2019 के तहत सीईसीए के अंतर्गत “रिफाइंड ब्लिचड डिओडोराइज्ड पाम आयल और “रिफाइंड ब्लिचड डिओडोराइज्ड पामोलीन” के आयात पर, अनन्तिम शुल्क के लगाए जाने की तारीख से 180 दिनों के लिए जो द्विपक्षीय रक्षोपाय शुल्क लगाया गया है वह वर्तमान परिस्थितियों के मद्देनजर पर्याप्त है और इस वर्तमान 180 दिन की अवधि के बाद भी किसी रक्षोपाय शुल्क को लगाए जाने की जरूरत नहीं है।

और अधिसूचना संख्या 22/4/2019, दिनांक 26 अगस्त, 2019 के तहत जारी प्रारंभिक निष्कर्षों की अभिपुष्टि की है और निम्नलिखित निर्णय लिया है कि :-

- (क) केन्द्र सरकार के द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 29/2019-सीमा शुल्क, दिनांक 4 सितम्बर, 2019 के तहत “रिफाइंड ब्लिचड डिओडोराइज्ड पाम आयल” और “रिफाइंड ब्लिचड डिओडोराइज्ड पामोलीन” के आयात पर लगाए जाने वाले अनन्तिम शुल्क की तारीख से 180 दिन की अवधि के लिए भारत-मलेशिया बृहद् आर्थिक सहयोग करार के अंतर्गत, अधिसूचना संख्या 22/4/2019, दिनांक 26 अगस्त, 2019 के तहत जारी प्राथमिक

निष्कर्षों में विनिर्दिष्ट रूप में और तरीके से विषयगत देश से होने वाले विषयगत वस्तु के आयात पर द्विपक्षीय रक्षोपाय शुल्क लगाया जाए।

(ख) उपर्युक्त निष्कर्षों को देखते हुए उक्त द्विपक्षीय रक्षोपाय शुल्क को आगे जारी रखने की कोई आवश्यकता नहीं है।

अतः अब, उक्त नियमावली के नियम 9 के साथ पठित सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, उक्त निर्दिष्ट प्राधिकारी के उपर्युक्त अंतिम निष्कर्षों पर विचार करने के पश्चात, एतद्वारा, मलेशिया में मूलतः उत्पादित और भारत-मलेशिया बृहद् आर्थिक सहयोग करार के अंतर्गत आयातित उक्त विषयगत वस्तु जो कि सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के टैरिफ मद [1511 90 10] या टैरिफ मद [1511 90 20] के अंतर्गत आती है, के आयात पर द्विपक्षीय रक्षोपाय शुल्क, जिसे कि भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 29/2019-सीमाशुल्क, दिनांक 4 सितम्बर, 2019, जिसे सा.का.नि. 632(अ), दिनांक 4 सितम्बर, 2019 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था के द्वारा लगाए गए और अधिसूचित किए गए ऐसे शुल्क की तारीख (अर्थात् 4 सितम्बर, 2019) से 180 दिन के लिए लगाए जाने को अभिप्रेष्ट करती है।

[फा. सं. 354/132/2019-टीआरयू]

गौरव सिंह, उप सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th May, 2020

No. 22/2020-Customs

G.S.R. 293(E).—Whereas the Directorate General of Trade Remedies (hereinafter referred to as the ‘designated authority’) in the matter concerning imports of “Refined Bleached Deodorized Palmolein and Refined Bleached Deodorized Palm Oil” (hereinafter referred to as the ‘subject goods’), falling under tariff item [1511 90 10] or tariff item [1511 90 20] of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) (hereinafter referred to as the Customs Tariff Act), initiated an investigation in terms of rule 9 of the India Malaysia Comprehensive Economic Cooperation Agreement (Bilateral Safeguard Measures) Rules, 2017 (hereinafter referred to as the said rules) *vide* notice of initiation Case No. (SG) 04/2019, dated the 14th August 2019, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-I, Section 1, dated the 14th August 2019.

And Whereas, in the preliminary findings issued *vide* notification (Bilateral Safeguard Investigation) case no (SG) 04/2019, dated the 26th August 2019, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-I, Section 1 dated the 26th August, 2019, the designated authority came to a preliminary conclusion that critical circumstances exist where delay in imposition of safeguard measures would cause irreparable damage to the domestic producers and recommended an increase in rate of duty of customs by 5 percent, for a period of 180 days, on imports of subject goods, originating in Malaysia and imported under India-Malaysia Comprehensive Economic Cooperation Agreement (hereinafter referred to as the ‘CECA’).

And Whereas, on basis of the aforesaid findings of the designated authority, the Central Government imposed provisional Bilateral Safeguard Duty on the subject goods *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 29/2019-Customs, dated the 4th September 2019, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 632 (E), dated the 4th September 2019 by making further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.53/2011-Customs, dated the 1st July, 2011, published in the Gazette of India, *vide* number G.S.R. 499 (E), dated the 1st July, 2011.

And Whereas, the designated authority in its final findings issued *vide* notification (Bilateral Safeguard Investigation) case no (SG) 04/2019, dated the 28th February 2020, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-I, Section 1, dated the 28th February 2020 has noted and made the following conclusions namely: -

- (a) when the investigation was underway, the Government amended the import policy of items under HS Code 151190 10 (Refined Bleached Deodorised palm oil, HS Code 151190 20 (Refined Bleached Deodorised Palmolein) and HS Code 151190 90 (others) *vide* Notification No. 39/2015-2020, dated the 8th January 2010 thus placing the subject goods under “Restricted” category.
- (b) that basic customs duty under Free Trade Agreement between the Governments of Member States of the Association of South East Asian Nations (hereinafter referred to as the ‘ASEAN FTA’) and the Republic of India (which includes Malaysia) and CECA has also changed w.e.f. 1st January, 2020 and the difference between crude palm oil and Refined Palmolein or Palm Oil is 7.5% in both these Agreements.
- (c) safeguard duty in the present agreement without similar duty under ASEAN FTA would mean a futile safeguard duty, as the consumers would utilise benefit under ASEAN FTA.
- (d) in view of the above stated facts, it is considered that the bilateral safeguard duty imposed *vide* notification No. 29/2019-customs, dated 4th September, 2019 under the CECA on the import of Refined Bleached Deodorised Palm Oil” and “Refined Bleached Deodorised Palmolein” for a period of 180 days from the date of imposition of the provisional duty is sufficient in the present circumstances and it may not be necessary to impose safeguard duty beyond the current period of 180 days.

and has confirmed the Preliminary Findings issued *vide* Notification No. 22/4/2019, dated the 26th August, 2019 and recommend that: -

- (a) bilateral safeguard duty may be imposed on imports of subject goods from the subject country in the form and manner described in the Preliminary findings issued *vide* Notification No. 22/4/2019 dated the 26th August, 2019 under the CECA on the import of Refined Bleached Deodorised Palm Oil” and “Refined Bleached Deodorised Palmolein” for a period of 180 days from the date of imposition of the provisional duty by the Central Government issued *vide* Notification No. 29/2019-Customs dated the 4th September, 2019.
- (b) in view of the above conclusions, no further extension of bilateral safeguard duty is required.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) read with rule 9 of the said Rules, the Central Government, after considering the aforesaid final findings of the designated authority, hereby confirms the imposition of bilateral safeguard duty on the subject goods falling under tariff item [1511 90 10] or tariff item [1511 90 20] of the First Schedule to the Customs Tariff Act, originating in Malaysia and imported under India-Malaysia Comprehensive Economic Cooperation Agreement for a period of 180 days from the date of initial imposition of such duty (i.e. the 4th of September 2019), and was notified *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 29/2019-Cus dated 4th September 2019, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 632 (E), dated the 4th September 2019.

[F. No. 354/132/2019-TRU]

GAURAV SINGH, Dy. Secy.